प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
29.07.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1945 बजे

मुख्य समाचार

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा– ऑपरेशन सिंदूर ने किया स्पष्ट– आतंकवादी हमला होने पर भारत अपनी शर्तों के मुताबिक देगा जवाब।
- प्रदेश मंत्रिमंडल ने पुलिस भर्ती में चिट्टा का डोप टैस्ट किया अनिवार्य– जलशक्ति विभाग में 12 साल की सेवा पूरी कर चुके जलरक्षक बनेंगे पंप अटेन्डेंट।
- मॉनसून की भारी वर्षा व बादल फटने से मंडी शहर में 3 लोगों की मृत्यु– प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए स्थायी नीति लाएगी सरकार।
- उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा– प्रदेश के विभिन्न बस अड्डों के रख–रखाव पर खर्च होंगे 7 करोड़ रूपये।

प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर यह स्पष्ट करता है कि भारत ने 3 बिंदुओं पर निर्णय लिया है। आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के जवाब में उन्होंने कहा कि यदि भारत पर कोई आतंकवादी हमला होता है, तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर और अपने समय पर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि अब कोई परमाणु ब्लैकमेल काम नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आतंकवाद का समर्थन करने वाली सरकारों और आतंकवादी मास्टरमाइंड को दो अलग–अलग संस्थाओं के रूप में नहीं देखेंगे। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान लोगों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया।

राज्यपाल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को राज्य की विकासात्मक पहलों, प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रदेश को हुए नुकसान और नशा मुक्त हिमाचल अभियान की प्रगति से अवगत करवाया। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को इस वर्ष मानसून के कारण मंडी जिला में बादल फटने और भूस्खलन से हुए व्यापक नुकसान की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि इन आपदाओं के कारण प्रभावितों के घर और कृषि भूमि को भारी नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने पुनर्वास कार्य सुनिश्चित करने के लिए प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। राज्य स्तरीय नशामुक्त हिमाचल अभियान के बारे में जानकारी देते हुए राज्यपाल ने बताया कि इस अभियान को पंचायत स्तर तक लागू किया जा रहा है।

कैबिनेट

राज्य सरकार नशे के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और इसी कड़ी में प्रदेश मंत्रिमंडल ने पुलिस भर्ती में चिट्टा का डोप टैस्ट अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की दूसरे दिन की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके लिए हर ज़िले में नशामुक्ति केंद्र खोले जाएंगे और राज्य कार्य योजना के तहत 14 करोड़ 95 लाख रूपये की योजना को मंजूरी दी गई है। बैठक में जलशक्ति विभाग में 12 साल की सेवा पूरी कर चुके जलरक्षकों को पंप अटेंडेंट बनाने का फैसला भी लिया गया। बैठक के बाद मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि इस निर्णय से 31 दिसंबर 2024 तक 12 साल पूरे कर चुके एक हज़ार 3 सौ 86 जलरक्षक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि इससे विभाग को 18 करोड़ का सालाना आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा। बैठक में नाहन, नालागढ़, मोहल और रोहडू में मिल्क प्रोसैसिंग प्लांट खोलने को भी मंजूरी दी गई। इस दौरान आपदा को लेकर कैबिनेट सब–कमेटी की सिफारिशों को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की।

सिकंदर कुमार

केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा एयरपोर्ट पर परिचालन करने वाली एयर लाइनों द्वारा किसी भी पर्यावरणीय खतरे की सूचना प्रदान नहीं की गई है। संसद में आज राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा महामंत्री डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा कांगड़ा एयरपोर्ट पर पक्षियों के टकराने की घटनाओं की रोकथाम संबंधी पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कांगड़ा एयरपोर्ट पर एक जुलाई 2023 और 30 जून 2025 के बीच 2 पक्षी या वन्य जीव के टकराने की सूचना मिली थी। डॉक्टर सिकंदर कुमार के एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में वर्ष 2025 के लिए आर.सी.ए. के तहत एक कार्य योजना को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने नदी तटों सहित पूरे राज्य में सड़क निर्माण गतिविधियों से निकलने वाले मलबे और कचरे के अवैध डंपिंग की निगरानी व रोकथाम के लिए प्रत्येक ज़िले में एक समिति का गठन किया है।

मौसम

प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मॉनसून की वर्षा रूक–रूक कर जारी है और कई स्थानों पर भारी वर्षा का समाचार है। मंडी जिले में बीती रात मूसलाधार बारिश व बादल फटने की 2 अलग–अलग घटनाओं में अब तक 3 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका है। इन घटनाओं में जहां दर्जनों घर व दुकानों में मलबा भर गया है, वहीं सैंकड़ों वाहन दब गए हैं। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि जेल रोड़ और जोनल अस्पताल क्षेत्र में सबसे अधिक

नुकसान हुआ है। भारी बारिश व भूस्खलन से अवरूद्ध हुए चंडीगढ़–मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग को आज शाम जोगनी मोड़ के पास वन–वे ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया है, जबकि मंडी–धर्मपुर मार्ग अभी भी अवरूद्ध है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मंडी के उपायुक्त को प्रभावितों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपारिक बातचीत में कहा कि इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार अब एक स्थायी नीति ला रही है, ताकि जान–माल के नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि भविष्य में अब कोई भी सरकारी संस्थान नदी–नालों के किनारे नहीं बनाया जाएगा और सभी सरकारी भवन सौ से डेढ़ सौ मीटर की सुरक्षित दूरी पर ही बनाए जाएंगे।

हमने देखा कि कई सरकारी संस्थान जो है नदी नालों के किनारे बना दिए जाते हैं और कह दिया जाता है यहां बना दो। साइट डेवलमेंट पर ही करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है। इस बारे में कमेटी बनेगी और जो भी सरकारी संस्थान की बिल्डिंग बनेगी वो नदी नालों से 100 से 150 मीटर की दूरी पर बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। और जो लोग नदी नालों के किनारे बसे हैं उसके लिए कमेटी का उच्च स्तरीय गठन किया है।

मौसम विभाग ने आज और कल यानि 30 जुलाई के लिए कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और चंबा ज़िलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और केवल घोषणाएं करने में व्यस्त हैं। मंडी शहर के जेल रोड़ में हुई बादल फटने की घटना का जायज़ा लेने के बाद उन्होंने कहा कि मंडी ज़िले में लगातार बादल फटने की घटनाओं ने एक माह में ही 15 सौ करोड़ रूपये से अधिक का नुकसान किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वर्ष 2023 के बाद केंद्र सरकार ने प्रदेश को आपदा राहत के लिए 5 करोड़ रूपये से अधिक की सहायता प्रदान की हैं। बावजूद इसके प्रभावितों को अभी तक राहत नहीं मिली है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ठाकुर ने सरकार को सिर्फ घोषणाओं तक सीमित न रहकर पीड़ितों तक राहत पहुंचाने के लिए ठोस व पारदर्शी कार्य योजना लागू करने का आग्रह किया है।

उप–मुख्यमंत्री

उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आज शिमला में राज्य पथ परिवहन निगम और बस अड्डा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक मंडल की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर उन्होंने निगम के कार्यों को और अधिक डिजिटल व प्रभावी बनाने के लिए 4 नए आई.टी. सॉफ्टवेयर का शुभारंभ भी

किया। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न बस अड्डों की मुरम्मत और रख–रखाव के लिए 7 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जाएगी और सभी बस अड्डों पर सी.सी.टी.वी कैमरे लगाए जाएंगे। निदेशक मंडल ने हिम बस प्लस नामक एक नई योजना शुरू करने को भी मंजूरी दी।

विरोध प्रदर्शन

प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों पर राज्य में सरकारी ज़मीनों से बेदखली और सेब के पेड़ों के कटान के विरोध में किसान सभा व सेब उत्पादक संघ के नेतृत्व में किसानों और बागवानों ने आज शिमला में सचिवालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार से बेदखली व घरों की तालाबंदी पर रोक लगाने की मांग की।

मुख्यमंत्री

बाद में पूर्व विधायक राकेश सिंघा के नेतृत्व में सेब उत्पादक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को विभिन्न मांगों व समस्याओं से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद सेब उत्पादकों का एक भी पेड़ काटने नहीं दिया जाएगा।

मुख्य समाचार एक बार फिर

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा– ऑपरेशन सिंदूर ने किया स्पष्ट– आतंकवादी हमला होने पर भारत अपनी शर्तों के मुताबिक देगा जवाब।
- प्रदेश मंत्रिमंडल ने पुलिस भर्ती में चिट्टा का डोप टैस्ट किया अनिवार्य– जलशक्ति विभाग में 12 साल की सेवा पूरी कर चुके जलरक्षक बनेंगे पंप अटेन्डेंट।
- मॉनसून की भारी वर्षा व बादल फटने से मंडी शहर में 3 लोगों की मृत्यु– प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए स्थायी नीति लाएगी सरकार।
- उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा– प्रदेश के विभिन्न बस अड्डों के रख–रखाव पर खर्च होंगे 7 करोड़ रूपये।